भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 270
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

देश में कार्यशील न्यायालयों (कोर्टरूम) की स्थिति

270 श्री महेश पोद्दार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क़) देश में कार्यशील न्यायालयों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कार्यशील हुए नवनिर्मित न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या देश में और आभासी (वर्चुअल) न्यायालयों की शीघ्रता से स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है तथा गत दो वर्षों के दौरान आभाषी अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 21,364 न्यायालय हाल 31.12.2021 तक उपलब्ध हैं । अन्य 2830 न्यायालय हाल निर्माणाधीन हैं । देश में उपलब्ध और निर्माणाधीन न्यायालय हालों का राज्य-वार विवरण **उपाबंध-1** पर है ।

(ख) : राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों ने सूचित किया है कि 2018-19 से 2020-21 तक 2060 नए न्यायालय हालों का निर्माण पूरा किया जा चुका है । उपरोक्त अवधि अर्थात् 2018-19 से 2020-21 के दौरान पूरा किए गए न्यायालय हालों के राज्य वार ब्यौरे **उपाबंध-2** पर है ।

(ग) : वीडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी) भौतिक सुनवाई के रूप में कोविड लोकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में आविर्भाव हुई है और सामूहिक रीति में सामान्य न्यायिक कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लोकडाउन के आरंभ होने के समय से ही, वीडियो कान्फ्रेसिंग का उपयोग करते हुए, तारीख 30.11.2021 तक जिला न्यायालयों ने 1,08,36,087 मामलों जब कि उच्च न्यायालय ने 57,39,966 मामलों (कुल 1.65 करोड़) की सुनवाई की । लोकडाउन अवधि के आरंभ के समय से ही तारीख 08.01.2022 तक उच्चतम न्यायालय ने 1,81,909 मामलों की सुनवाई की, जो इसे वीडियो कान्फ्रेसिंग सुनवाई में विश्व अग्रणी बनाता है । वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा 3240 न्यायालयों और तत्स्थानी वीडियो कान्फ्रेसिंग 1272 कारागारों के बीच भी प्ररिचालित की गई है । 2506 वीडियो कान्फ्रेसिंग कैबीन स्थापित करने के लिए निधि उपलब्ध कराई गई है । अतिरिक्त 1500 वीडियो कान्फ्रेसिंग अनुज्ञप्तियां अर्जित की गई है ।

19.01.2022 तक यातायात संबंधी अपराधों के विचारण के लिए 17 वर्चुअल न्यायालय 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2),

असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए गए है । पारम्परिक न्यायालयों की इमारतों से विमुख होकर वर्चुअल न्यायालयों की स्थापना की जाती हैं जो वर्चुअल इलैक्ट्रानिक मंच पर एक न्यायाधीश द्वारा प्रशासित किए जाते हैं, जिसकी अधिकारिता संपूर्ण राज्य पर विस्तारित हो सकेगी और वह 24X7 घंटे कार्य कर सकेंगे । इन न्यायालयों ने 1.2 करोड़ मामलों की सुनवाई की है और 212.01 करोड़ रुपए की जुर्माने के रूप में वसूली की है ।

****

उपाबंध-1

देश में कार्यशील न्यायालयों (कोर्टरूम) की स्थिति से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 270 जिसका उत्तर तारीख 03.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(31.12.2021 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपलब्ध कुल न्यायालय हाल	निर्माणाधीन कुल न्यायालय हाल
1	अंदमान और निकोबार	17	0
2	आंध्र प्रदेश	623	102
3	अरुणाचल प्रदेश	24	2
4	असम	391	94
5	बिहार	1558	98
6	चंडीगढ़	31	0
7	छत्तीसगढ़	464	27
8	दादरा और नागर हवेली	3	0
9	दमण और दीव	5	0
10	दिल्ली	553	140
11	गोवा	53	28
12	गुजरात	1505	210
13	हरियाणा	555	70
14	हिमाचल प्रदेश	168	9
15	जम्मू - कश्मीर	194	43
16	झारखंड	1280	26
17	कर्नाटक	1162	89
18	केरल	534	35
19	लद्दाख	9	0
20	लक्षद्वीप	3	0
21	मध्य प्रदेश	1530	393
22	महाराष्ट्र	2350	297
23	मणिपुर	39	0
24	मेघालय	53	35
25	मिजोरम	42	26
26	नागालैंड	30	12
27	ओडिशा	798	84
28	पुडुचेरी	36	0
29	पंजाब	589	40
30	राजस्थान	1306	226
31	सिक्किम	20	1
32	तमिलनाडु	1190	58
33	तेलंगाना	499	26
34	त्रिपुरा	88	6
35	उत्तर प्रदेश	2591	446
36	उत्तराखंड़	235	66
37	पश्चिमी बंगाल	836	141
कुल		**21364**	**2830**

उपाबंध-2

देश में कार्यशील न्यायालयों (कोर्टरूम) की स्थिति से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 270 जिसका उत्तर तारीख 03.02.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

2018-19 से 2020-21 तक पूर्ण किए गए न्यायालय हालों का राज्य वार विवरण		
क्र. सं.	**राज्य और संघ राज्यक्षेत्र**	**पूर्ण किए गए न्यायालय हाल**
1	अंदमान और निकोबार	2
2	आंध्र प्रदेश	16
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	23
5	बिहार	191
6	चंडिगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	35
8	दादरा और नागर हवेली	0
9	दमण और दीव	2
10	दिल्ली	120
11	गोवा	28
12	गुजरात	108
13	हरियाणा	39
14	हिमाचल प्रदेश	0
15	जम्मू और कश्मीर	6
16	झारखंड़	39
17	कर्नाटक	328
18	केरल	48
19	लद्दाख	0
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	214
22	महाराष्ट्र	219
23	मणिपुर	0
24	मेघालय	12
25	मिजोरम	0
26	नागालैंड	0
27	ओडिशा	141
28	पुडुचेरी	23
29	पंजाब	41
30	राजस्थान	157
31	सिक्किम	1
32	तमिलनाडु	125
33	तेलंगाना	26
34	त्रिपुरा	0
35	उत्तर प्रदेश	77
36	उत्तराखंड़	5
37	पश्चिमी बंगाल	34
कुल		**2060**

****